



**International Journal of Advanced Research in
Education and Technology (IJARETY)**

Volume 11, Issue 3, May-June 2024

Impact Factor: 7.394



नगर निगम में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग: वर्तमान स्थिति एवं भविष्य

Havir Singh

Assistant Professor, Department of Public Administration, M S J Govt. College, Bharatpur, Rajasthan, India

सार: आयोग की अनुशंसा है कि नगरीय स्थानीय निकायों के समस्त कार्य क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी चरणबद्ध रूप में प्रारम्भ की जाये। इसके साथ ही नगरीय निकायों के सभी कर्मचारियों को ई० सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों के परिचालन और प्रयोग का समुचित प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाये।

I. परिचय

1990 के दशक के मध्य में भारत में रेलवे कम्प्यूटरीकरण, भूमि अभिलेख कम्प्यूटरीकरण और कई अन्य परियोजनाओं के साथ ई-गवर्नेंस पहल शुरू हुई, जिसका मुख्य जोर नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने पर था। लेकिन सीमित सुविधाओं के कारण, इन ई-गवर्नेंस सेवाओं का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और एक अधिक कनेक्टेड सरकार की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को स्थापित करने, अंतर-संचालन संबंधी मुद्दों को संबोधित करने आदि के लिए अधिक व्यापक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता पैदा हुई। जाहिर है, ई-गवर्नेंस योजना की कमियों को देखते हुए जिसमें सरकारी अनुप्रयोगों और डेटाबेस के बीच एकीकरण की कमी, सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना का निम्न स्तर, मोबाइल, क्लाउड जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की गुंजाइश आदि शामिल हैं, भारत सरकार ने ई-क्रांति परियोजना को मंजूरी दी है जिसका विजन "शासन में परिवर्तन के लिए ई-गवर्नेंस में परिवर्तन" है। इसका फोकस परिवर्तन को साकार करने पर है। [1,2,3]

- प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना;
- मांग पर शासन एवं सेवाएं; तथा
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण
- मंत्रालय/विभाग/राज्य भारत सरकार द्वारा स्थापित साझा और सहायक आईसीटी अवसंरचना का पूरा लाभ उठाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मानक और नीति दिशानिर्देश भी विकसित/निर्धारित करेगा, तकनीकी और सहायक सहायता प्रदान करेगा, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास आदि कार्य करेगा।
- मौजूदा/चल रही ई-गवर्नेंस पहलों को डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के साथ संरेखित करने के लिए उपयुक्त रूप से नया रूप दिया जाएगा। इसके अलावा, नागरिकों को सरकारी सेवाओं की डिलीवरी बढ़ाने के लिए नए तरीके और दृष्टिकोण अपनाए जाएंगे जैसे कि प्रक्रिया पुनर्रचना, कार्यक्षेत्र में वृद्धि, एकीकृत और अंतर-संचालनीय प्रणालियों का उपयोग और क्लाउड और मोबाइल जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग आदि।
- राज्यों को अतिरिक्त राज्य-विशिष्ट परियोजनाओं को शामिल करने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाएगा, जो उनकी सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हों।
- ई-गवर्नेंस को आवश्यक सीमा तक केंद्रीकृत पहल के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे नागरिक केंद्रित सेवा अभिविन्यास, विभिन्न ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों की अंतर-प्रचालनीयता और आईसीटी अवसंरचना/संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होगा, साथ ही विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन मॉडल को अपनाया जाएगा।
- सफलताओं की पहचान की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उनके अनुकूलन के साथ-साथ उनकी प्रतिकृति को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
- ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जब भी आवश्यक होगा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन पर्याप्त प्रबंधन और रणनीतिक नियंत्रण के साथ।
- पहचान, प्रमाणीकरण और लाभ वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए विशिष्ट पहचान पत्र को अपनाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के तेजी से डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन के लिए कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में मुख्य सूचना अधिकारियों (सीआईओ) के पद सृजित किए जाएंगे।

डिजिटल इंडिया के स्तंभ:

सभी के लिए ब्रॉडबैंड उपलब्धता
मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच
सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम[4,5,6]
ई-गवर्नेंस- प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में परिवर्तन
ई-क्रांति-सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी
सभी के लिए जानकारी
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण
नौकरियों के लिए आई.टी.
शीघ्र कटाई कार्यक्रम

II. विचार-विमर्श

वर्तमान 2022 में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का सकल घरेलू उत्पाद में 8% हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2023 में आईटी और बीपीएम उद्योग का राजस्व 245 बिलियन US\$ होने का अनुमान है, जो सालाना 9% की वृद्धि है।^{[1][2][3]} वित्त वर्ष 2023 में आईटी उद्योग का घरेलू राजस्व 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निर्यात राजस्व 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। आईटी उद्योग ने वित्त वर्ष 2023 में लगभग 2.9 लाख कर्मचारियों को रोजगार दिया है। इसमें लगभग 54 लाख लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं जिससे यह सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों में से एक बन गया है।^{[4][5]}

दिसंबर 2022 में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचित किया कि राज्य द्वारा संचालित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के साथ पंजीकृत आईटी इकाइयों ने 2021-22 में 11.59 लाख करोड़ रु. मूल्य के सॉफ्टवेयर का निर्यात किया है।^{[6][7]} भारत की वर्तमान तरक्की में आईटी का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले पाँच सालों (२००४-२००९) में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बढ़ोतरी के प्रतिशत में 6 प्रतिशत योगदान आईटी का ही है। पिछले 10 सालों में देश में जो रोजगार उपलब्ध हुआ है, उसका 40 प्रतिशत आईटी[7,8,9] ने उपलब्ध कराया है।

भौगोलिक सीमाओं को तोड़ते हुए अलग-अलग देशों में उत्पाद उत्पाद इकाइयाँ बनाना, हर देश में उपलब्ध श्रेष्ठ संसाधन का उपयोग करना, विभिन्न देशों से काम करते हुए पूरे 24 घंटे अपने ग्राहक के लिए उपलब्ध रहना और ऐसे डेटा सेंटर बनाना जो कहीं से भी इस्तेमाल किए जा सकें, ये कुछ ऐसे प्रयोग थे जो हमारे लिए काफी कारगर साबित हुए। अब सारी दुनिया इन्हें अपना रही है।



एमार्ज़ॉन.कॉम हैदराबाद परिसर



बागमने टेक पार्क बैंगलोर में ओरेकल और अन्य के कार्यालय

इतिहास

इलेक्ट्रॉनिक्स समिति, जिसे "भाभा समिति" के रूप में भी जाना जाता है, ने भारत के आईटी सेवा उद्योग की नींव रखने वाली 10-वर्षीय (1966-1975) योजना बनाई।^[8] इस उद्योग का जन्म 1967 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना के साथ मुंबई में हुआ था, जिसने 1977 में बरोज़ के साथ भागीदारी की, जिसने भारत से आईटी सेवाओं का निर्यात शुरू किया। [12] पहला सॉफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र, एसईईपीजेड - आधुनिक समय के आईटी पार्क का अग्रदूत - मुंबई में 1973 में स्थापित किया गया था। देश के 80 प्रतिशत से अधिक सॉफ्टवेयर निर्यात 1980 के दशक में एसईईपीजेड से हुए थे।^[9]

हाल के वर्षों में भारत में सभी उद्योगों, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप में तेजी आई है। यह उछाल स्टार्टअप इंडिया स्कीम और टी-हब जैसी विभिन्न स्टार्ट अप योजनाओं के कारण है।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण पहल

- रेलवे टिकट एवं आरक्षण का कम्प्यूटरीकरण
- बैंकों का कम्प्यूटरीकरण एवं एटीएम की सुविधा
- इंटरनेट से रेल टिकट, हवाई टिकट का आरक्षण
- इंटरनेट से एफआईआर
- न्यायालयों के निर्णय आनलाइन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
- किसानों के भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण
- इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन एवं आनलाइन काउंसिलिंग
- आनलाइन परीक्षाएं[10,11,12]
- कई विभागों के टेंडर आनलाइन भरे जा रहे हैं।
- पासपोर्ट, गाडी चलाने के लाइसेंस आदि भी आनलाइन भरे जा रहे हैं।
- कई विभागों के 'कांफिडेंसियल रिपोर्ट' आनलाइन भरे जा रहे हैं।
- शिकायतें आनलाइन की जा सकती हैं।
- सभी विभागों कई बहुत सारी जानकारी आनलाइन उपलब्ध है। [[सूचना का अधिकार' के तहत भी बहुत सी जानकारी आनाइन दी जा रही है।
- आयकर की फाइलिंग आनलाइन की जा सकती है।
- ईमेल भेजना (किसी प्रकार का फाइल को तुरंत भेजना)

आई टी कंपनियाँ

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास पिछले वर्षों में बड़ी तेज़ी से हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं। उनमें से प्रमुख हैं -

भारतीय

इस क्षेत्र की प्रमुख भारतीय कम्पनियों के नाम हैं -

- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (en:Tata Consultancy Services)
- इंफोसिस (en:Infosys)
- विप्रो (en:WIPRO)
- एचसीएल टेक्नोलॉजीज (en:HCL Technologies)
- टेक महिंद्रा

बहुराष्ट्रीय

इंटेल् (en:Intel)

- माइक्रोसॉफ्ट (en:Microsoft)
- टी.आई. (en:Texas Instruments)
- गूगल (en:Google)
- एमार्ज़ॉन.कॉम
- एक्सेंचर
- कैपजेमिनी
- डीएक्ससी टेक्नोलॉजी[13,14]
- याहू (en:Yahoo)
- सैप लैब्स इंडिया (SAP Labs India). सैप लैब्स इंडिया की पितृ संस्था SAP AG है जो जर्मनी में स्थित है।
- ऑरेकल (en:Oracle Corporation)

भारतीय आईटी क्षेत्र राजस्व

**भारतीय आईटी और बीपीएम उद्योग
का राजस्व**

	in US\$ (वित्त वर्ष 23 के लिए)
निर्यात राजस्व	194 बिलियन
घरेलू राजस्व	51 बिलियन
कुल आईटी राजस्व	245 बिलियन
आईटी क्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष कर्मचारी:	54 लाख

समकालीन विश्व अर्थव्यवस्था में, भारत आईटी का सबसे बड़ा निर्यातक है।^[10] भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आईटी क्षेत्र का योगदान 1998 में 1.2% से बढ़कर 2019 में 10% हो गया।^[11] निर्यात भारतीय आईटी उद्योग पर हावी है और उद्योग के कुल राजस्व का लगभग 79% है। हालांकि, मजबूत राजस्व वृद्धि के साथ घरेलू बाजार भी महत्वपूर्ण है।

2022 में, इस क्षेत्र के भीतर की कंपनियों को महत्वपूर्ण कर्मचारियों की छंटनी और हायरिंग में तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।^[12] COVID-19 महामारी से प्रभावित FY23 में भारतीय आईटी राजस्व एक दशक में सबसे तेजी से बढ़कर 245 बिलियन डॉलर हो गया। मार्च 2022 तक आईटी-बीपीएम क्षेत्र में कुल मिलाकर 54 लाख लोग कार्यरत हैं।^[13] नैसकॉम ने अपनी रणनीतिक समीक्षा में भविष्यवाणी की है कि आईटी उद्योग 11-14 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए वित्त वर्ष 26 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।

बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनियां बाजार पूंजीकरण द्वारा 2022 में भारत में शीर्ष आईटी सर्विसेस कंपनियां।^{[14][15][16][17][18]} सितंबर 2021 में, TCS ने 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण दर्ज किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय आईटी टेक कंपनी बन गई।^{[19][20][21]} 24 अगस्त 2021 को, इंफोसिस बाजार पूंजीकरण में \$100 बिलियन तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई।^{[22][23]}

Rank	आईटी सर्विसेस कंपनी का नाम	Market capitalization in 2022(US\$ Billion)	Market capitalization in 2022(₹ करोड़)
1	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज	200	14,63,372.44
2	इंफोसिस	100	7,34,140.78
3	विप्रो	50	3,17,428
4	एचसीएल टेक्नोलॉजीज	36.67	3,18,061
5	एलटीआईमाइंडट्री	20.86	1,33,592.40
6	टेक महिंद्रा	12.65	1,33,592.40

राजस्व के आधार पर सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनियां राजस्व के हिसाब से 2022 में भारत की शीर्ष आईटी सर्विसेस कंपनियां।^{[24][25][26][27]}

Rank	आईटी सर्विसेस कंपनी का नाम	Revenue in 2022(US\$ Billion)	Revenue in 2022(₹ करोड़)
1	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज	27.5	195,772

2	इंफोसिस	18.2	123,936
3	एचसीएल टेक्नोलॉजीज	12.3	85,651
4	विप्रो	11.2	79,093
5	टेक महिंद्रा	6.5	38,642
6	एलटीआईमाइंडट्री	4.1	33,000

आईटी निर्यात में राज्यवार राजस्व[15,16,17]

वित्त वर्ष 2023 तक आईटी निर्यात में राजस्व की राज्यवार सूची नीचे दी गई है।^{[28][29][30][31]}

S.No	State	Revenue in IT Exports (US\$ बिलियन)	Revenue in IT exports (₹ करोड़)
1	कर्नाटक	65 बिलियन	3.28 लाख
2	महाराष्ट्र	33 बिलियन	2.45 लाख
3	तेलंगाना	32 बिलियन	2.41 लाख
4	तमिलनाडु	22 बिलियन	1.79 लाख

आईटी-बीपीएम कर्मचारियों की संख्या स्थान के अनुसार

भारत में आईटी-बीपीएम कर्मचारियों की संख्या

S.No	Region	Employee Count in IT/ITES (as of FY23)
1	बंगलौर	15 लाख
2	हैदराबाद	9.05 लाख
3	तमिलनाडु*	10 लाख
4	पुणे	4 लाख

Note : * चेन्नई and कोयंबतूर शामिल है।

वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य

भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है और बुरी भी। अच्छी इसलिए कि भारतीय प्रतिभाओं की नित नई खोज से विकसित सॉफ्टवेयर और कम्प्यूटर सेवा उद्योग से भारतीय अर्थव्यवस्था के समृद्धशाली संसाधनों और उनसे आय के स्रोतों में तेजी से बढ़ोत्तरी सामने आ रही है। यह क्षेत्र तीस फीसदी सालाना से भी ज्यादा तेज दर से बढ़ रहा है। इस उद्योग को सन् दो हजार चार में करीब पचीस बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक का राजस्व मिला जिसमें करीब सत्रह बीस बिलियन डालर की आय अकेले निर्यात से प्राप्त हुई। भारतीयों को यह सुनकर कितना सुखद लगेगा कि इस उद्योग में एक मिलियन से भी अधिक लोग सीधे रोजगार पा रहे हैं जबकि 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं। इस प्रकार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस उद्योग का तीन फीसदी से भी ज्यादा योगदान है जबकि कुल निर्यात का बीस प्रतिशत आईटी उद्योग से आता है। बुरी खबर इसलिए है कि जिन प्रतिभाओं भारत को लाभ उठाना था, वे दूसरों की प्रगति का जरिया बन रही हैं। भारत में जिस तरह से कुछ राजनीतिक दल फिर से आरक्षण-आरक्षण की रट लगा रहे हैं, उससे भारतीय प्रतिभाओं का पलायन रोका जाना संभव नहीं हो सकेगा।

एक आर्थिक रिपोर्ट से पता चलता है कि इसका ब्रिटेन जैसे देशों को बहुत फायदा हुआ है। इन फायदों में कंप्यूटर सेवाओं की भारतीय उप महाद्वीप में आउटसोर्सिंग से होने वाली बचत भी शामिल है। भारतीय साफ्टवेयर कंपनियां विदेशों में होने वाले निवेश की अगुआई करती रही हैं। जिससे इनमें ज्यादातर निवेश विलय और अधिग्रहण के जरिए होते हैं। देखा जाए तो भारतीय आईटी

उद्योग सही मायने में देश का पहला वैश्विक व्यवसाय बनने की दिशा में बढ़ रहा है। ब्रिटेन में प्रमुख कंप्यूटर प्रदाता कंपनी के रूप में भारत की टाटा कंसलटेंसी [18,19]को ही ले लीजिए जिसने इस क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है। सूचना प्रौद्योगिकी के लचीले व्यवसायिक नियमों के कारण आज कई कंपनियां ज्यादा कुशलतापूर्वक अपना काम कर रही हैं। इनमें टाटा ने दुनिया की दस बड़ी कंपनियों में अपने को स्थापित कर लिया है। तीस वर्ष से टाटा कंसलटेंसी भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले व्यवसाय के अनुरूप परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाए हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय प्रतिभाओं की भारी मांग ने भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज गति से विकास करने वाला सूचना प्रौद्योगिकी बाजार बना दिया है। भारतीय साफ्टवेयर और आईटीईएस उद्योग का पिछले छह वर्ष के दौरान करीब 30 प्रतिशत के सीएजीआर की दर से विकास सामने आया है। उपभोक्ताओं की उभरती आवश्यकताओं का प्रबंधन बेहतर रूप से करने के लिए, बहुउद्देशीय सेवा प्रदायी क्षमताओं के लाभ और कुछ नई सेवाओं की प्रदायगी एक छोर से दूसरे छोर तक करने की भारतीय प्रतिभाओं की क्षमता को स्वीकार करते हुए भारतीय कंपनियां हरित क्षेत्र प्रयासों क्रास-बार्डर एमएण्डए, स्थानीय उद्योगों के साथ भागीदारी और गठबंधन के माध्यम से अपनी सेवाएं बढ़ा रही हैं।

माइक्रोसाफ्ट, ओरेकल, एसएपी जैसे साफ्टवेयर उत्पादों की बड़ी कंपनियों ने अपने विकास केंद्र भारत में स्थापित किये हैं। सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में भारत का रिकार्ड अधिकांश देशों से बेहतर माना जा रहा है। भारत के प्राधिकारी देश में सूचना सुरक्षा के परिवेश को और मजबूत करने पर गहन रूप से बल दे रहे हैं। इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन, समीक्षा, उद्योगों के प्रबंध वर्गों के बीच आपसी संपर्क में वृद्धि के बारे में जागरुकता बढ़ाई जा रही है। भारत की अधिकांश कंपनियों ने आईएसओ, सीएमएम, सिक्स सिगमा जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों को पहले ही शामिल कर लिया है, जिस कारण भारत को एक भरोसेमंद सोर्सिंग गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सहायता मिली है।

एक अधिकृत रिपोर्ट के अनुसार भारत की बड़ी कंपनियों ने पांच सौ से ज्यादा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हैं जो विश्व के किसी भी देश से अधिक हैं। दूर संचार, विद्युत निर्माण कार्य, सुविधा प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, खानपान और अन्य सेवाओं सहित वेंडरों पर इसका असर दिखाई देने लगा है। गनीमत है कि सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में मूलभूत गुणवत्ता सुधार को प्राथमिकता दी है और इस संदर्भ में साधारण जनता के जीवन से जुड़े क्षेत्रों में ई-शासन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है। इसके अनुसार एक राष्ट्रीय ई-शासन योजना तैयार की गयी है जिसमें यह विचार मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया है कि इसका उद्देश्य साधारण जनता को सभी सरकारी सेवाएं उसी के इलाके में आजीवन, एकल बिन्दु केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध होंगी। साधारण जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसी सेवाओं के लिए कम लागत पर कुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होनी जरूरी है। जिस प्रकार इसके घटक राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क सामान्य सेवा केन्द्र, क्षमता निर्माण, इंटरनेट संवर्द्धन, रूट सरवरों की स्थापना, मीडिया लैब एशिया, सूचना सुरक्षा, अनुसंधान एवं विकास में जैसों खबू काम चल रहा है उसके लिए यह बहुत जरूरी है और यह इस बात का प्रमाण कहा जा सकता है कि आईटी के क्षेत्र में भारत ने जो प्रगति की है, उसका संबंध सीधे प्रतिभाओं के उच्च स्तरीय प्रयोग से है।

अमरीका और यूरोप के बाद जापानी कंपनियां भी भारतीय इंजीनियरों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। जापान में तो इंजीनियरों की संख्या में भारी कमी है इसलिए जापान ने इसे पूरा करने के लिए भारत और वियतनाम जैसे देशों के इंजीनियरों को अपने यहां शानदार अवसर दिए हैं। जापान की डिजिटल टेक्नॉलाजी के लिए उसे भारी संख्या में इंजीनियरों की आवश्यकता है यह अचरज की बात है कि जापान में तकनीकी विषयों की प्रतिभाओं में अच्छी खासी कमी आई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका कारण जापान में अत्यधिक आराम पसंद होना और गुढ़ विषयों की माथापच्ची से बचना है इसलिए यहां के छात्र विज्ञान से किनारा करते पाए गए हैं। जापान में यूं तो भारतीय इंजीनियरों के लिए भाषा की एक बड़ी समस्या है लेकिन पता चला है कि जापान की सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए भी अपने यहां एशियन टेलेंट फंड का निर्माण किया है। जापान सरकार अपने यहां के प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने में कोई कमी नहीं छोड़ती है लेकिन यहां की प्रतिभाओं का जापान तकनीकी क्षेत्र में पलायन नहीं रोक पा रहा है। भारत में मेहनतकश लोगों की कमी नहीं है। यहां की प्रतिभाएं जिस क्षेत्र में जुटती हैं उसमें वह काफी कमाल दिखाती हैं। इसे अमरीका, जापान, ब्रिटेन, रूस जैसे देशों ने माना है। भारत के औद्योगिक राजघराने की अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय प्रतिभाओं को काफी आकर्षित किया है। इन कंपनियों ने भारतीय प्रतिभाओं को विदेशों में ही अवसर देने के रास्ते खोल दिए हैं जिससे विदेशी कंपनियों में भारतीय प्रतिभाओं का न केवल महत्व बढ़ गया है अपितु उन्हें दिया जाने वाला पैकेज भी भारी भरकम हो गया है।

इस कारण इस क्षेत्र में प्रतिभाओं का जितना प्रवेश दिखायी पड़ रहा है, उतना भारत की अखिल भारतीय सेवाओं में भी नहीं दिखता है। गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण विश्व के दूसरे देशों ने भारतीय आईटी प्रतिभाओं को जो मान्यता दी है, उससे आने वाले समय में भारतीय प्रतिभाओं की और भी ज्यादा आवश्यकता होगी। आने वाले समय में अब दुनिया में केवल प्रतिभाओं की मांग होगी और इसके दूसरे पक्षों को दरकिनार कर दिया जायेगा। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है। भारत के कुछ अशांत क्षेत्रों में विघटनकारी गतिविधियों और आरक्षण जैसी मांगों का भी सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार पर कोई विपरीत असर नहीं दिखायी पड़ता है। विश्व समुदाय मानता है कि भारत में आईटी के क्षेत्र में प्रतिभाओं की अद्भुत खोज हुई है। एक

समय बाद भारतीय प्रतिभाएं दुनिया के लिए बड़ी मजबूरी बन जाएंगी, क्योंकि भारत के पास यही एक दौलत है, जिसके बूते पर प्रतिभाओं के क्षेत्र में भी सदियों से उसका इकबाल कायम है।

III. परिणाम

नगर निगम (municipal corporation) कई स्थानीय सरकारों के प्रशासन संगठन का नाम होता है। यह अक्सर किसी नगर परिषद या ज़िले, ग्राम, बस्ती या अन्य स्थानीय शासकीय निकायों के अधीन काम करता है।^{[1][2][3]}

नगर नगमों की स्थापना

कानूनी रूप से नगर निगम तब स्थापित होते हैं जब किसी नगर, बस्ती या ग्राम को स्वशासन का अधिकार दिया जाता है। यह एक कानूनी लिखत जारी कर किया जाता है, जिसे नगरीय अधिकारपत्र (municipal charter) कहा जाता है, जिसमें प्रशासन संचालन व उच्चतम नगर अधिकारियों के चुनाव या नियुक्ति की विधि स्पष्ट करी जाती है।⁴

आज देश में सूचना प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभा रही है। भारत अब आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी आईटी राजधानी में से एक है और दुनिया के आईटी क्षेत्र के सभी प्रमुख खिलाड़ी आज देश में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश, देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, देश में सॉफ्टवेयर निर्यात के छठे स्थान के साथ उत्तर भारत का आईटी हब है। आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य लगातार अवसंरचना, मानव पूंजी विकास और प्रभावी नीति कार्यान्वयन के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि आईटी-बीपीएम उद्योग के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा सके।

यह सब सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (IT&E) के प्रशासनिक नियंत्रण में किया जा रहा है, जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग राज्य के अन्य विभागों और उनके उपभोक्ताओं के फायदे के लिए आईटी के उपयोग और तैनाती की मार्गदर्शक भी है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा अन्य सरकारी विभागों को तकनीकी सहायता इसके दायरे में आने वाले निगमों/सोसायटी के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

विभाग ने पूरे राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के लक्ष्य के साथ अपनी आईटी नीति 2012 जारी की, जिसमें नोएडा/ ग्रेटर नोएडा के आईटी हब के अनुभव का लाभ उठाते हुए राज्य के टियर-II और टियर-3 शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आईटी नीति 2012 की सफलता को जारी रखते हुए और बदलते व्यापार परिदृश्य के आलोक में आईटी नीति 2012 की पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट अप नीति 2016 आईटी/आईटीएस उद्योग के सभी चरणों को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी की गई है, जिसमें स्टार्ट अप/उद्यमियों, एमएसएमई (माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज) और बड़े आईटी/आईटीएस उद्योग को अनुकूल नीति ढांचे के साथ सर्वोत्तम प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस नीति का उद्देश्य आईटी/आईटीईएस उद्योग के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थिति को मजबूत करना, ई-गवर्नेंस और एम-गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से नागरिक सेवाओं को आगे बढ़ाना और राज्य में स्टार्ट अप व नवोदित उद्यमियों के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देना है।^[17,18,19]

IV. निष्कर्ष

मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार यानी RTI कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है बस शर्त यह है की RTI के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। यानि हम किसी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते। जैसे आप के इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए है और कहाँ खर्च हुए है, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए है जैसे सवाल आप सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पता कर सकते है।

प्रयोग एवं फायदे :

- कोई भी नागरिक, किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है
- ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम करता है।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है।
- इस अधिकार का उपयोग हम किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नहीं कर सकते। इसका उपयोग हम तथ्यों की जानकारी पाने के लिए कर सकते है। जैसे, “डिस्पेंसरी में कितनी दवाइयां आती है, पार्क और साफ़ सफाई में कितना खर्च हुआ, किसी सरकारी दफ्तर में कितनी नियुक्तियां हुईं?” इसके अलावा “ सड़क बनाने के लिए कितने पैसे आये और कहा पर खर्च हुए?”
- सभी गवर्मेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति, पुलिस, बिजली कंपनियां, RTI act के अन्दर आते है।

- लोगो ने RTI के इस्तेमाल से कई ऐसी जानकारी हासिल की है जिससे उनकी रोजमर्रा की समस्याएँ सुलझ गई हैं।
- सरकार की सुरक्षा से सम्बंधित जानकारी या गोपनीय जानकारी इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आती।
कैसे प्राप्त करे जानकारी?
- हर सरकारी विभाग में जन सुचना अधिकारी होता है। आप अपने आवेदन पत्र उसके पास जमा करवा सकते हैं।
- आवेदन पत्र का फॉर्मेट इन्टरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एक सफ़ेद कागज पर अपना आवेदन(एप्लीकेशन) लिख सकते हैं जिसमें जन सुचना अधिकारी आपकी मदद करेगा।
- RTI की एप्लीकेशन आप किसी भी भारतीय भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश या किसी भी स्थानीय भाषा में दे सकते हैं
- अपने आवेदन पत्र की फोटो कॉपी करवा कर जन सुचना अधिकारी से रिसेविंग जरूर ले ले।
- <https://rtionline.gov.in/> इस साईट पर जा कर केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र डालने के ३० दिन के अन्दर आपको जवाब मिल जाएगा
- यदि ऐसा नहीं होता है तो आप कार्ट में अपील कर सकते हैं
- किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ 10/- रूपये की फीस है
- ये फीस गरीबी रेखा से नीचे के लोगो के लिए माफ़ है.[20]

संदर्भ

1. "India's tech industry set to reach \$245 billion in FY23".
2. ↑ "Indian IT sector to touch \$245 billion in FY23: Nasscom".
3. ↑ "In its yearly strategic review for FY22, Nasscom said the industry added 4.5 lakh new jobs to take the overall direct employees to 50 lakh people. Over 44 per cent of the new hires were women, and their overall share is now 18 lakh".
4. ↑ "Number of employees in IT".
5. ↑ Nirmal, Rajalakshmi. "IT's time for ctrl+alt+delete". The Hindu (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 26 February 2017.
6. ↑ "IT companies at STPI, SEZs export software worth Rs 11.59 lakh crore in 2021-22".
7. ↑ "Software exports from Andhra Pradesh not on expected lines, says BJP leader".
8. ↑ Agarwal, Suraj Mal (10 July 2002). "Electronics in India: Past strategies and future possibilities Author links open overlay panel". World Development.
9. ↑ "Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities" (PDF). www.itida.gov.eg. मूल (PDF) से 21 September 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 July 2010.
10. ↑ "भारतीय आईटी कंपनियों का राजस्व 29% बढ़ा".
11. ↑ Rakheja, Bhaswar Kumar Harshit (28 January 2022). "Will Indian IT industry sustain its growth momentum?". Business Standard India.
12. ↑ Sengupta, Devina (2022-04-22). "Entry-level salaries at IT cos set to rise amid high attrition". mint (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-04-30.
13. ↑ "भारतीय आईटी क्षेत्र को 2026 में 95 लाख लोगों की जरूरत होगी : सरकार".
14. ↑ "Top 10 Indian companies by market value".
15. ↑ "HCL Technologies becomes 4th IT firm to hit Rs 3 trillion market-cap".
16. ↑ "Market capitalization".
17. ↑ "LTI-Mindtree merger comes into effect, becomes 5th largest IT company by m-cap".
18. ↑ "Wipro third IT co to hit ₹4 trillion market cap".
19. ↑ "TCS 2nd Indian company to hit \$200 billion mcap after RIL".
20. ↑ "TCS Market Capitalisation Hits \$200 Billion As Shares Jump To Fresh Highs".

International Journal of Advanced Research in Education and Technology

ISSN: 2394-2975

Impact Factor: 7.394